भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2885

18.03.2025 को उत्तर के लिए नियत

ईवी विनिर्माण इकाइयों की स्थापना और उद्योग विकास

2885. श्री सप्तगिरी शंकर उलाका:

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले वर्ष से भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) और संबंधित कलपुर्जों के लिए विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने वाली कंपनियों की संख्या राज्यवार कितनी है;

(ख) ईवी विनिर्माण क्षेत्र में कुल कितना निवेश हुआ है और क्या यह मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के तहत सरकार के लक्ष्यों के अनुरूप है;

(ग) ईवी निर्माताओं को प्रदान की जाने वाली राजसहायता, प्रोत्साहन और कर लाभ की सीमा क्या है और क्या इनसे वास्तविक रोजगार सृजन हुआ है और घरेलू उत्पादन में वृद्धि हुई; और

(घ) क्या सरकार ने ईवी क्षेत्र के विकास, विशेष रूप से बैटरी उत्पादन के स्थानीयकरण, चार्जिंग संबंधी बुनियादी ढांचे के विस्तार और आयात निर्भरता में कमी के संदर्भ में कोई प्रभाव का मूल्यांकन किया है और यदि हां, तो इसके निष्कर्ष क्या हैं?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) और (ख) : भारी उद्योग मंत्रालय केंद्रीय रूप से ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखता।

(ग) : सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन विनिर्माताओं की सहायता के लिए कई कदम उठाए हैं जिनके कारण रोज़गार सृजन हुआ है और घरेलू उत्पादन बढ़ा है। विवरण निम्नानुसार हैः-

i. **ऑटोमोबिल और ऑटो घटक संबंधी उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (पीएलआई-ऑटो):** सरकार ने उन्नत ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी (एएटी) उत्पाद के मामले में भारत की विनिर्माण क्षमता बढ़ाने के लिए ऑटोमोबिल और ऑटो संघटक उद्योग हेतु 25,938 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता वाली इस स्कीम को 23.09.2021 को मंज़ूरी दी।

ii. **राष्ट्रीय उन्नत रसायन सेल (एसीसी) बैटरी भंडारण कार्यक्रम विषयक उत्पादन-संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीमः** सरकार ने देश में एसीसी विनिर्माण हेतु पीएलआई स्कीम को 12.05.2021 को अनुमोदित किया ताकि आयातित बैटरियों पर निर्भरता घटे और भारत की स्वच्छ ऊर्जा तथा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी अंगीकरण को सहायता देने के लिए उन्नत रसायन सेल के स्थानीय उत्पादन को प्रोत्साहन देकर घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा दिया जा सके। इस स्कीम के अंतर्गत 50 गीगावाट घंटा क्षमता के लिए 2 वर्ष के गेस्टेशन के बाद 5 वर्ष की अवधि हेतु कुल बजटीय परिव्यय 18,100 करोड़ रुपए है।

(घ) : ऐसा कोई अध्ययन नहीं किया गया है।

***